OBC reservations in the seats surrendered by them to the all-India quota to the detriment of the OBC students.

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion?

SHRI P. WILSON: This has led to a huge loss to the students of OBC, BC and MBC categories. In the recently concluded PG admissions, 8,137 seats were in the all-India quota. If 27 per cent seats were applied to these seats, 2,197 seats should have been allowed to the OBC candidates. However, shockingly, only 224 seats were allotted. This is because of the lacuna which I described. The hardship has been intensified by the recent Constitutional Amendment to EWS reservation. Our party has already stood against its reservation for upper class, since it is not in accordance...

MR. CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI P. WILSON: Therefore, there is a...

MR. CHAIRMAN: You are a new Member. After the time is over, even if I keep quiet and you are making your point, that will not go on record. Please take note that it is automatic. That is why I was cautioning you. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. WILSON: Sorry, Sir. Kindly permit me. ...*(Interruptions)*... One minute, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, it cannot be. ...*(Interruptions)*... Shrimati Sampatiya Uikey; not present. ...*(Interruptions)*... Shri Shwait Malik. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Please allow him, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will not go against the rules. ...*(Interruptions)*... I will not go against this. ...*(Interruptions)*... You also please sit down. ...*(Interruptions)*... You persuade him, you are a senior Member. ...*(Interruptions)*... You should have guided him before time. In a discussion, I can allow beyond the time, but on this, it is not done.

Need to restrict overcharging by private schools

SHRI SHWAIT MALIK (Punjab): Sir, I demand for a strict policy to restrict overcharging by some private schools in Punjab. सर, यह बहुत अत्याचार हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप दो मिनट ही बोलिएगा, बाद में सुरेन्द्र सिंह नागर जी हैं।

श्री श्वेत मलिक: कुछ लोगों ने स्कूल को एक दुकान बनाकर रख दिया है। इस दुकान के माध्यम से जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वे स्कूल के प्रोफेशन में आ रहे हैं। उनका मकसद

शिक्षा देना नही, बल्कि पैसा कमाना है। सर, स्कूल में donations के नाम पर सबसे भारी donation ली जाती है। आज हर व्यक्ति लोन लेकर भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे उच्च शिक्षित करना चाहता है। मोदी जी ने लोगों को जो मोटिवेट किया है, यह सब उसके कारण है, पर ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये उसका अलग-अलग platforms पर शोषण करते हैं। Donation के बाद इनकी बिल्डिंग फीस आ जाती है। उस बेचारे का तो घर बनता नही है, लेकिन इनकी एक के बाद एक कई स्कूलों की बिल्डिंग्स बन जाती हैं। उसके बाद बुक्स आ जाती हैं। वह जाकर कही से भी किताबें खरीदे, लेकिन ये उसे चार-चार गुणा अधिक मूल्य पर किताबें खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि स्कूल से ही बुक्स मिलेंगी। Uniform दरज़ी को सिलनी हैं, वह uniform दरज़ी से मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल में यह रूल बन जाता है कि uniform खरीदोगे, तो चार गुणा मूल्य पर ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आपका सुझाव क्या है? What is your demand?

श्री श्वेत मलिक: उसके बाद कभी ये tours के माध्यम से, कभी scientific labs के माध्यम से उसका खून तक चूसते हैं।

सर, मेरी यह डिमांड है कि throughout the country, basically इसकी सबसे ज्यादा जाँच करने की जरूरत है कि एक स्कूल के बाद इनके दस-दस स्कूल कैसे खुल जाते हैं? वे स्कूल बढ़ते जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Surendra Singh Nagar. ...*(Interruptions)*...

श्री श्वेत मलिक: सर, मेरी यह डिमांड है कि इस पर एक strict policy बने और उस policy के माध्यम से ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Your demand has gone on remand now. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Shwait Malik, you have to follow the Chairman. ...*(Interruptions)*... When I caution you, you should understand. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली की मनमानी की तरफ दिलाना चाहता हूं।

महोदय, यदि 2005 से लेकर अब तक का आंकड़ा लें, तो लगभग 150 परसेंट की वृद्धि प्राइवेट स्कूलों की फीस में हुई है। इसके अलावा विभिन्न मदों पर, जिसके बारे में पूर्व साथी

ने बताया है, पैसा उगाहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन उस कानून का उत्तर प्रदेश में आज तक अनुपालन नही हो पा रहा है। खास तौर से नोएडा, जो सबसे नजदीक का शहर है, वहाँ अभिभावक इस कानून का लाभ लेने के लिए आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे कभी DM से मिलते हैं, कभी DIS से मिलते हैं, लेकिन उनको इस कानून का संरक्षण नही मिल पा रहा है। आपके माध्यम से सरकार से मेरी request है कि वह देश में इन private schools की fees की मनमानी को रोकने के लिए कोई कानून बनाए, जिससे अभिभावकों और बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बी. के. हरिप्रसाद (कर्नाटक): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. सी. पी. ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

†**جناب محمد علی خان (آندھرا پردیش) :** مہودے، میں بھی خود کو مانّئے سدسئے کے ذریعے اٹھائے گئے وشئے کے ساتھ سمبدّھ کرتا ہوں۔

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

†Transliteration in Urdu Script.

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापति: दोला सेन जी, आपको भी पि. भट्टाचार्य जी के साथ समय share करना पड़ेगा, इसलिए आप समय को ध्यान में रखिए।

Need to review decision to privatise Indian Ordnance Factories

MS. DOLA SEN (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise this matter. The Indian Ordnance Factories Organisation is a family of 41 ordnance factories, 25 hospitals, 24 schools, and nine training institutes, with the Ordnance Factory Board, headquartered in Kolkata. It possesses the unique distinction of over 200 years experience in defence production. Indian ordnance factories is the oldest and largest industrial set up which functions under the Department of Defence Production of the Ministry of Defence.

It has been recently reported that the Government has decided to corporatise Indian ordnance factories which will eventually lead to its privatisation. To the best of my knowledge, the Government has not held any consultations with any stakeholders as well.